रुपयाकी मजबूती

यह संतोषका विषय है कि भारतीय मुद्रा रुपयेकी स्थिति अब मजबूत हो गयी है। साथ ही रुपया एशियाकी बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओंमें शामिल हो गया है। यह देशकी अर्थव्यवस्थाके सन्दर्भमें अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। अन्तरराष्ट्रीय बाजारमें डालरके मुकाबले रुपयेकी स्थिति किसी देशके आर्थिक स्वास्थ्य, विदेशी निवेशकोंका भरोसा, व्यापार सन्तुलन और मौद्रिक स्थिरताका महत्वपूर्ण संकेतक है। ऐसे समयमें जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक तनाव, तेलकी कीमतोंमें उतार-चढ़ाव, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और अमेरिकी मौद्रिक नीतियोंके प्रभावसे गुजर रही है, रुपयेकी मजबूती भारतके लिए सकारात्मक सन्देश भी देती है। इसके बावजूद रुपयेकी मजबूतीको केवल आर्थिक सफलताका प्रमाण मानना अभी उचित नहीं माना जा सकता है। यह भी जानना आवश्यक है कि इसके पीछे कौनसे कारक काम कर रहे हैं और इसका भारतीय अर्थव्यवस्थाके विभिन्न क्षेत्रोंपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चालू वित्त वर्षमें पहली बार भारतीय रुपये .९७ प्रतिशत मजबूत हुआ है। इससे पहले मईमें रुपया ९६.९६ प्रति डालरके रिकार्ड निचले स्तरतक पहुंच गया था। अक्तूबरमें भी यह ९७ के निचले स्तरके करीब पहुंचा था। नवम्बरके दूसरे सप्ताहमें रुपयेने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। ११ नवम्बरको रुपया डालरके मुकाबले लगभग ९३.७५ के स्तरपर पहुंच गया। पिछले कुछ दिनोंसे इसमें लगातार सुधार देखनेको मिला। ६ नवम्बरको रुपया ९३.९१ प्रति डालरपर बंद हुआ था। यह छह माहका उच्च स्तर था। अक्तूबरमें रुपयेने लगभग एक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। रुपयेमें मजबूतीके कई बड़े कारण भी हैं। कच्चे तेलकी कीमतोंमें गिरावट एक प्रमुख कारण है। तेलकी कीमतें बढ़नेसे भारतको अधिक डालर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपयेपर दबाव बढ़ता है। तेल सस्ता होनेसे आयात बिल घटता है। पश्चिम एशियामें तनाव कम होनेकी सम्भावनाओंने भी बाजारकी धारणाको प्रभावित किया है। विदेशी निवेशकोंकी वापसीसे रुपयेमें मजबूती आयी है। विदेशी निवेशक अब भारतीय शेयर बाजारमें उल्लेखनीय खरीदारी कर रहे हैं। अमेरिकी निवेशकोंका रुझान एआई और उससे जुड़ी कम्पनियोंपर बढ़ा है। इसके अतिरिक्त रुपयेमें उतार-चढ़ावको रोकनेके लिए भारतीय रिजर्व बैंकने भी सक्रियता बढ़ायी है। रुपयेमें मजबूतीसे आयात अब सस्ता होगा। महंगीपर भी एक सीमातक नियंत्रण होगा। विदेशी कर्जका बोझ घटेगा। विदेशमें पढ़ाई और यात्रा सस्ती होगी। इन सबके बाद भी रुपयेके सामने भविष्यकी चुनौतियां भी हैं। इसलिए इससे निबटनेके लिए भारतको प्रभावशाली रणनीति बनानी होगी। रुपया आगे भी मजबूत बना रहे, इसपर भी सोचना होगा।

ढाकामें फिर भड़की हिंसा

बंगलादेशमें तख्तापलटके बाद अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीनाके वतन वापसीसे पूर्व शुरू हुई हिंसक झड़पोंके दौरके निहितार्थको समझनेकी जरूरत है। शेख हसीना इस समय भारतमें है और उन्होंने इसी साल दिसम्बर माहमें स्वदेश लौटनेका ऐलान किया है। इसको लेकर देशमें तनाव अपने चरमपर है। इस बढ़ती हलचलके बीच हिंसा और आगजनीकी वारदातोंने लोगोंको झकझोर कर रख दिया है। एक ओर जहां देशके भविष्यकी राजनीतिको लेकर चर्चाएं गर्म हैं वहीं दूसरी ओर हिंसाका खौफनाक रूप भी दिख रहा है जिससे जन-सामान्य दहशतमें है। राजधानी ढाका और आसपासके कई जिलोंमें देर रात अचानक हिंसा भड़क उठी। हसीनाकी पार्टी अवामी लीग समर्थकों और विरोधियोंके बीच कई जगहोंपर हिंसक झड़पें हुईं। इन घटनाओंमें एक व्यक्तिकी मौत हो गयी, जबकि आठ वाहनोंको आगके हवाले कर दिया गया। कई जगहोंपर देसी बमसे धमाके किये गये, जो बंगलादेशकी बदतर होते हालातको बयां करते हैं। पुलिसने इन घटनाओंके लिए प्रतिबिन्धित अवामी लीग और उससे जुड़े संघटनोंके कार्यकर्ताओंको जिम्मेदार ठहराया है। वहीं मंगलवारको बंगलादेशमें प्रतिबन्धित छात्र लीगकी देशव्यापी बंदके बीच भी कई जिलोंमें हिंसा भड़क उठी। खगराछड़ी जिलेमें अज्ञात हमलावरोंने बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक वार्ड कार्यालयमें आग लगा दी। शरियातपुर जिलेमें एक टोल प्लाजापर जमकर तोड़फोड़ की गयी जिससे यातायात पूरी तरह बाधित रहा। इसी तरह नेत्रकोनामें एक्सप्रेस ट्रेनके एक डिब्बेमें आग लगायी गयी जिसपर समय रहते आगपर काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियोंके अनुसार इन घटनाओंमें अवामी लीग समर्थकोंका हाथ होना बताया जाता है। दरअसल अवामी लीगको डर है कि शेख हसीनाके बंगलादेश पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायगा और उन्हें फांसी दे दी जायगी। वैसे क्या होगा यह तो भविष्यके गर्भमें है लेकिन फिलहाल ढाकाके जो हालात हैं, वह बेहद चिन्तनीय है। भारतको भी बंगलादेशके हालातपर पैनी नजर रखनी होगी।

लोक संवाद

विज्ञानका उचित प्रयोग

महोदय,- दस नवंबरको अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और विकास भी है। अर्थात् शांति और विकासके कामोंमें विज्ञानकी भूमिकाके प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यदि विज्ञानका उचित प्रयोग किया जाय तो यह प्राणी जातिके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और अनुचित प्रयोग अभिशाप भी बन जाता है। विज्ञानने इनसानकी जिन्दगी बहुत आरामदायक बना दी है। संचार क्रांति, डिजिटल क्रांति और अन्य बहुत-सी भौतिकतावादी वस्तुएं जो विज्ञानकी तरफसे हमें मिली हैं, वह हमारे लिए सुख तो पहुंचाती हैं, लेकिन इनमेंसे बहुत-सी हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। विज्ञान और नयी तकनीकका प्रयोग उचित तरीकेसे किया जाय तो वो वरदान है, अन्यथा वह अभिशाप बनेगी। -**राजेश कुमार, लखनऊ।**

सोशल मीडियापर अंकुश जरूरी

पिछले कुछ वर्षोंमें दुनियाने कई देशोंमें सत्ता परिवर्तन देखे हैं, जिनमें बंगलादेश, श्रीलंका और नेपाल प्रमुख हैं। इन देशोंमेहुए सत्ता परिवर्तनोंमें एक बात समान थी- सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन, जिन्हें सोशल मीडियाके जरिये हवा मिली। इन देशोंमें नागरिकोंको उद्वेलित करनेमें सोशल मीडियाने अहम भूमिका निभायी।

❐ डा. अश्वनी महाजन

सोशल मीडियाने चर्चाओंको और तेज कर दिया है कि श्रीलंकामें विरोध-प्रदर्शनोंके कारण अंतत: राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेको इस्तीफा देना पड़ा। बंगलादेशमें चुनी हुई प्रधान मंत्री शेख हसीनाको देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपालका 'जेन-जी' आन्दोलन भी इससे कुछ अलग नहीं था। वहां भी, सोशल मीडियाने खराब शासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाबदेही और बेरोजगारीसे जुड़ी चर्चाओंको बढ़ावा दिया। नेपालमें युवा प्रदर्शनकारियोंको एकजुट करने और सूचनाएं फैलानेमें सोशल मीडियाने बड़ी भूमिका निभायी। साथ ही इसका इस्तेमाल आधिकारिक बयानोंको चुनौती देनेके लिए भी किया गया। यह आन्दोलन सितंबर २०२५ में प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओलीके इस्तीफेके साथ समाप्त हुआ। एक बड़ी चिन्ता यह है कि जहां सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपनी तकनीकका इस्तेमाल सरकारोंको जवाबदेह ठहरानेके लिए करते हैं, वहीं इन प्लेटफार्म्सकी खुदकी जवाबदेही तय करनेके लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। यहांतक कि जब इन प्लेटफार्म्सका गलत आचरण सामने आता है, तब भी उनके खिलाफ कोई सख्त काररवाई करना सम्भव नहीं होता।



फेसबुक और इंस्टाग्रामका भारतमें कुल सोशल मीडिया वेब ट्रैफिकमें ७० प्रतिशतसे ज्यादा हिस्सा है। मेटाका डिजिटल विज्ञापन नेटवर्क और सार्वजनिक सूचनाओंके प्रवाहपर भारी नियंत्रण है। सामान्य तौरपर सरकारें सोशल मीडिया कम्पनियोंके कुकृत्योंके बाद ही उनपर अंकुश लगानेकी बात सोचती हैं, लेकिन तबतक भारी नुकसान हो जाता है। उदाहरणके लिए इस बातका आभास होते ही कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म प्रदर्शनको अधिक महत्व दे रहे हैं, नेपालमें सितंबर २०२५ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ह्वाट्सएप और यूट्यूब सहित २६ सोशल मीडिया प्लेटफार्मपर प्रतिबंध लगा दिया गया।

भारत सरकारके पास इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाईडलाईंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियमावली २०२१ के अंतर्गत नियम ४ (२) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) और यौन अपराधों या बच्चोंके यौन शोषणसे संबद्ध कुछ संगीन अपराधोंके संदर्भमें यह अधिकार है कि संदेशके प्रारम्भ कर्ताकी पहचान कर सके और अपराधियोंको दंड दे सके। नियममें यह भी प्रावधान है कि ऐसा तब किया जायगा जब कम सख्त तरीके प्रभावी सिद्ध नहीं हो पायें। गौरतलब है कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफार्म निजताके नामपर नियमोंको भी माननेसे इनकार करते हैं। न्यायालयमें सुनवाईके दौरान एक बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ह्वाट्सएप आदि सोशल मीडिया कम्पनी 'मेटा' के प्रमुख मार्क जुकरबर्गने बयान दिया था कि यदि उन्हें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समाप्त करनेके लिए बाध्य किया जायगा तो वह भारतसे निकल जायंगे, यानी इन सोशल मीडिया सेवाओंको भारतमें समाप्त कर देंगे। उनके इस बयानसे यह समझा जा सकता है कि भारत सरकार उन्हें कुछ हिदायत दे रही है, जिनका वे पालन नहीं करना चाहते और इसलिए अपने इस बयानसे जनतामें राय बनाते हुए भारत सरकारपर दबाव बनाना चाहते हैं कि वह उनपर अंकुश न लगाये। क्या है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और क्या हैं भारतीय नियम- मेटाका कहना है कि ह्वाट्सएप द्वारा भेजे गये सन्देश एंड टू एंड एन्क्रिप्टिड, यानी एक सिरेसे दूसरे सिरेतक गुप्त होते हैं, यानी सिर्फ वही व्यक्ति जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं, वही आपके मैसेज पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टिड होती है। अब जब भारत सरकार संगीन अपराधोंके लिए ह्वाट्सएपसे जानकारी मांगती है तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन यानी निजताका हवाला देकर, ह्वाट्सएप उससे बचना चाहता है। दूधकी धुली नहीं है मेटा- एक ओर जहां मेटा कम्पनी ऊंचे आदर्शोंका दंभ भरते हुए भारत सरकारके नियमोंको माननेसे यह कहकर इनकार कर रही है कि इससे उसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन समाप्त हो जायगी और यह उनकी वैश्विक स्तर वैशिष्ट्य है, जिसके लिए ह्वाट्सएप दुनियामें जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर यह कम्पनी यूजर्सका डाटा बिना उनकी अनुमतिके अन्य लोगोंको कीमतके बदले उपलब्ध कराती रहती है।

यूजर्स डाटाको बेचनेकी प्रक्रियाको सरल बनानेके लिए कम्पनीने अपनी प्राइवेसी नीतिमें भी बदलाव किया है। इस बदलावके साथ मेटाने स्वयंको अधिकृत किया कि वह अन्य मेटा कम्पनियोंके साथ उनका डेटा साझा कर सकती है। २०२१ में किये गये बदलावमें यह प्रावधान था कि जो ग्राहक ऐसा नहीं चाहते, वे उनकी सेवा छोड़ सकते हैं। मेटाका यह भी कहना था कि इससे उसकी सेवाओंमें पारदर्शिता बढ़ी है। बादमें भारतकी नियामक संस्था कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने कहा कि यह बदलाव कि यदि उन्हें डाटा साझा करना स्वीकार नहीं तो वे मेटा सेवा छोड़ सकते हैं, अनुचित है। आयोगने कहा कि यह डेटा साझा करना ह्वाट्सएप सेवाओंके उपलब्ध करानेसे संबद्ध नहीं है और उसने मेटापर २१३ करोड रुपयेसे अधिकका जुर्माना लगाया और उसके बदलावको रोक कर उपभोक्ताओंके चयनके अधिकारको बहाल किया। इतिहासमें ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मेटा कम्पनीने ग्राहकोंकी निजी जानकारियोंका अनुचित उपयोग किया।

कैंब्रिज एनालेटिका घोटालेमें फेसबुकके लाखों यूजर्सका डाटा किसी तीसरी एपके माध्यमसे लेकर उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। इन लाखों यूजर्सने अपने इस डाटाका उपयोग करनेके लिए अनुमति नहीं दी थी। २०१९ में अमेरिकाके फेडरल ट्रेड कमीशनने निजता हननके लिए फेसबुकपर पांच अरब डालरका जुर्माना लगाया। २०२१ में फ्रांसिस हॉगनने इंस्टाग्रामके आंतरिक दस्तावेजोंका खुलासा करते हुए इंस्टाग्रामके किशोरोंके मानसिक और अन्य प्रकारसे स्वास्थ्यपर पड़ने वाले दुष्प्रभावोंके बारेमें बताया और यह साबित किया कि मेटा कम्पनीका इस बाबत रुख गैर-जिम्मेदाराना रहा। २०१८ में संयुक्त राष्ट्रके फैक्ट फाईंडिंग मिशन द्वारा यह बताया गया कि फेसबुक सामाजिक घृणा फैलानेमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। बे-रोकटोक सोशल मीडियाके माध्यमसे इस प्रकारकी घृणा फैलनेके कितने दुष्परिणाम होते हैं, यह उसका उदाहरण है। म्यांमारमें फेसबुकपर सोशल मीडिया पोस्टोंने एक अल्पसंख्यक समुदायके खिलाफ घृणाका वातावरण तैयार किया।

मेटा द्वारा विभिन्न प्रकारके अधिग्रहण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियोंके कारण अलग-अलग देशोंमें सोशल मीडियाके क्षेत्रमें प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो गयी है। खास तौरपर फेसबुक द्वारा इंस्टाग्राम और ह्वाट्सएपके अधिग्रहणके बाद सोशल मीडियामें मेटाका एकछत्र राज्य स्थापित हो चुका है। अबतक यह स्पष्ट हो चुका है कि मेटा कम्पनी यूजर डाटाको ट्रेक करते हुए लक्षित विज्ञापन भी करती है। ह्वाट्सएपके माध्यमसे मेटा कम्पनी गलत जानकारियां प्रसारित करनेका काम करती है और ऐसा देखा गया है कि ह्वाट्सएपपर फैली अफवाहोंकी वजहसे दंगे, उत्पीड़नकी गतिविधियां तो होती ही हैं और तथाकथित एंड टू एंड एनक्रिप्शनकी वजहसे यह पता नहीं चल पाता कि गलत सूचनाओंका स्रोत क्या है। वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टमपर मेटाका लगभग एकाधिकार है। रोजाना ३.५ अरबसे ज्यादा सक्रिय यूजर्स इसके विभिन्न ऐपसपर मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ह्वाट्सएप और थ्रेड्सको एक साथ जोड़कर, मेटा कम्पनी संचारके प्रमुख माध्यमोंको नियंत्रित करती है। अकेले फेसबुक और इंस्टाग्रामका भारतमें कुल सोशल मीडिया वेब ट्रैफिकमें ७० प्रतिशतसे ज्यादा हिस्सा है। मेटाका डिजिटल विज्ञापन नेटवर्क, डेटा इकट्ठा करनेकी प्रक्रिया और सार्वजनिक सूचनाओंके प्रवाहपर भारी नियंत्रण है। सामान्य तौरपर सरकारें सोशल मीडिया कम्पनियोंके कुकृत्योंके बाद ही उनपर अंकुश लगानेकी बात सोचती हैं, लेकिन तबतक भारी नुकसान हो जाता है। उदाहरणके लिए इस बातका आभास होते ही कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म प्रदर्शनको अधिक महत्व दे रहे हैं, नेपालमें सितंबर २०२५ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ह्वाट्सएप और यूट्यूब सहित २६ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मपर प्रतिबंध लगा दिया गया।

लोकतंत्रके लिए बेहद घातक

वास्तविक लोकतंत्र वहीं होता है, जहां सत्तापक्ष विपक्षके सवालोंके जवाब दे। देशमें सत्तापक्षका मुखिया प्रधान मंत्री होता है, इसलिए सवालोंका अंतिम पड़ाव भी प्रधान मंत्री होता है।

❐ योगेन्द्र

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीपर सत्तामें आनेके बादसे लगातार विपक्ष और पत्रकारोंके सवालोंकी उपेक्षाके आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप सिर्फ भारतमें ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भी लगे हैं। इतना ही नहीं, विपक्षकी आवाज दबानेके आरोपोंका सामना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभाके सभापतिको करना पड़ा है। सर्वाधिक आश्चर्यकी बात यह है कि पीएम मोदीने कभी भी विपक्षके आरोपोंका सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे मौकोंपर पीएम मोदीके बजाय भाजपाके नेता और मंत्री ही सवालोंके जवाब आरोपोंके अन्दाजमें देते रहे हैं। पीएम मोदी मनकी बात या दूसरे मुद्दोंपर सोशल मीडियाका ही उपयोग करते रहें हैं। संसद और बाहर उठाये गये सवालोंके जवाबमें सत्तारूढ़ भाजपाने उल्टे सवाल पूछकर मुद्दोंको गोलमोल करनेका प्रयास किया है। विपक्ष यही आरोप संसद सत्रके दौरान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभाके सभापतिपर लगाता रहा है। राहुल गांधीने तीन दिनमें चार बार पीएमको मुद्दोंपर बहस करनेकी चुनौती दी। राहुल गांधीने प्रधान मंत्री मोदीपर विदेशी ताकतोंके दबावमें काम करनेका आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोदी विपक्षपर देशविरोधी होने और विदेशी ताकतोंसे संबंध रखनेके आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें इन मुद्दोंपर खुली बहस करनी चाहिए। राहुलने बहसके लिए भारत-अमेरिका ट्रेड डील, देशकी आर्थिक व्यवस्था, उद्योगपति गौतम अडाणी और जेफ्री एपस्टीनसे जुड़े मुद्दे उठाये।

उन्होंने कहा कि बहसमें देशके युवा और मीडिया भी मौजूद रहें। प्रधान मंत्री अपनी पसंदकी जगह और जज चुन सकते हैं। राहुल गांधीने संसदकी कार्यवाहीको लेकर भी सरकारपर सवाल उठाये। उनका आरोप है कि सरकार चर्चाकी बात करती है, लेकिन विपक्षको अपनी बात रखनेका मौका नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब वे बोलनेकी कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधीने प्रधान मंत्री मोदीको खुली बहसकी चुनौती दी। इसी तरह राहुलने वीडियो जारी कर कहा कि मोदीको बहसकी चुनौती दिये २४ घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफसे जवाब नहीं आया। पंजाबके संगरूरमें कांग्रेसकी इंसाफ रैलीमें राहुलने फिर मोदीको चुनौती दी। राहुलने दावा किया कि पांच मिनटकी बहसमें वे साबित कर देंगे कि मोदी 'देशद्रोही' हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पके नियंत्रणमें हैं। राहुलके सवालोंपर केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजूने जवाब देनेके बजाय उल्टे सात सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि यदि राहुल इन बातोंपर अमल करें तो कांग्रेस संसदमें ज्यादा सीटें जीत सकती है। रिजिजूने कहा, राहुलको भाजपाको दुश्मन नहीं, राजनीतिक विरोधी समझना चाहिए। उन्हें भाजपा, आरएसएस और प्रधान मंत्री मोदीके प्रति नफरत छोड़कर संसदकी कार्यवाहीमें हिस्सा लेना चाहिए। केन्द्रीय मंत्रीने संसदका एक पुराना वीडियो भी शेयर किया। इसमें वे भाषण दे रहे हैं और विपक्षी सांसद सदनसे उठकर जाते दिख रहे हैं। राहुल पहले भी बहसकी चुनौती दे चुके हैं। राहुलने अगस्त २०१८ में कर्नाटकके बेलगाममें जनध्वनि रैलीमें राफेल मुद्देपर कहा था कि मोदी और मेरे बीच राफेलपर बहस करा दो, मैं घंटों बोलूंगा। जनवरी २०१९ में राहुल गांधीने कहा कि राफेलपर लोकसभामें मुझे पीएमके साथ २० मिनट वन-टू-वन बहस करने दो, अमेरिकाके प्रेसिडेंशियल डिबेटकी तरह। साथ ही कहा था कि पीएममें हिम्मत नहीं है। ७ अप्रैल, २०१९ को भ्रष्टाचारपर मेनिफेस्टो लांचपर मोदीके एक इंटरव्यूके बाद राहुलने ट्वीट किया था कि आप भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते, मैं आपको भ्रष्टाचारपर बहसकी चुनौती देता हूं।

गौरतलब है कि २०२४ चुनावसे पहले भी राहुल समेत विपक्षने पूर्व जजों (मदन लोकुर, एपी शाह) के जरिये पीएमको लेटर लिखकर नेशनल सिक्योरिटी, अडानी, इलेक्टोरल बाण्डपर डिबेटको कहा था, जिसपर पीएमओकी ओरसे कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहने अपने दस सालके कार्यकालके दौरान संसदको ४८ बार संबोधित किया था। तब गुजरातके सीएम रहे नरेन्द्र मोदीने उन्हें 'मौन मोहन' कहा था। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी संसदमें अबतक २२ बार ही बोले हैं। एचडी देवगौड़ा जो सिर्फ करीब दो सालके लिए प्रधान मंत्री थे, उन्होंने भी संसदमें मोदीसे ज्यादा बार बोला था। बीजेपीके ही अटल बिहारी वाजपेयीने भी छह सालोंमें ७७ बार संसदको संबोधित किया था। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके यूरोप दौरेमें प्रेसके सवाल न लेनेके फैसलेपर विवाद रहा है। नॉर्वेके प्रधान मंत्री जोनस गार स्टोरेके साथ संयुक्त प्रेस वार्ताके दौरान नॉर्वेकी एक महिला पत्रकारने प्रधान मंत्री मोदीसे मीडियाके सवालोंका जवाब देनेका आग्रह किया था। लेकिन पीएम मोदीने कोई सवाल नहीं लिया था। नॉर्वेकी महिला पत्रकार हेला लेंगने विदेश मंत्रालयकी ब्रीफिंगमें भी मानवाधिकारोंको लेकर सवाल उठाये। इसपर विदेश मंत्रालयके एक वरिष्ठ अधिकारीने कहा कि भारत एक सिवलाइजेशनल नेशन है। इससे पहले हेला लेंगने ओस्लोके गवर्नमेंट गेस्ट हाउसमें प्रधान मंत्री मोदी और प्रधान मंत्री स्टोरकी प्रेस ब्रीफिंग खत्म होनेके बाद खड़े होकर सवाल पूछा था।

हेलाने पूछा था कि प्रधान मंत्री मोदी, आप दुनियाकी सबसे स्वतंत्र प्रेसके सवाल क्यों नहीं लेते। क्या आप हमारी सरकारके विश्वास के योग्य हैं। पीएम मोदीने इन सवालोंका कोई जवाब नहीं दिया था। हेलाके सवालपर भारतमें भी काफी बहस रही। तब भी लोकसभामें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधीने प्रधान मंत्रीको आड़े हाथों लिया और पूछा कि सवालोंसे घबरा क्यों रहे हैं। इन विवादोंको सुलझानेके लिए विदेश मंत्रालयने भारतके लोकतंत्रका बचाव किया। पीएम मोदीके इस दौरेमें दूसरी बार था, जब इन मुद्दोंपर सरकारको सफाई देनी पड़ी। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी २०२६ के वर्ल्ड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांकमें भारतको १८० देशोंमें १५७वां स्थान मिला है। इससे भारतकी अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। सत्तामें बहुमतके बूते विपक्ष और मीडियाकी आवाजको अनसुना करना देशके लोकतंत्रके लिए बेहद घातक है। इससे कहीं न कहीं सरकारी तंत्रमें तानाशाही पनपनेकी संभावना रहती है। यही कारण भी है कि देशमें भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, सरकारी तंत्रका गैर-जिम्मेदारी वाला आचरण नजर आता है। लोकतंत्रके लिए बेहतर तो यही होगा कि मोदी विपक्षके साथ-साथ मीडियाके सवालोंका भी जवाब दें।



स्वधर्मकी यात्रा

❐ ओशो

कैसे पहचानें कि मैंने किसी परधर्मको तो नहीं पकड़ लिया है। पहचान हो तो सकती है परन्तु पहचानके सूत्र सूक्ष्म होंगे। पहला सूत्र यह कि यदि आप जीवनमें दुखी हैं तो पक्का समझ लेना कि आप स्वधर्मसे हट गये हैं या हट रहे हैं। जहां भी स्वधर्मकी यात्रा होती है, वहीं आनन्द होता है। यदि अशांत हैं तो समझना चाहिए कि परधर्मके पीछे चल रहे हैं। रुककर दोबारा सोचना चाहिए कि जो यात्रा चुनी, जो कर रहे हैं, उससे दुख और पीड़ा, अशांति बढ़ती है तो निश्चित ही वह मार्ग मेरा नहीं है। शांति बढ़े तो आप स्वधर्मके निकट चल रहे हैं। शांति मापदंड है। दूसरा, यदि कोई स्वधर्मके साथ-साथ चल रहा हो तो उसके जीवनमें स्वीकारका भाव बढ़ेगा, अस्वीकार कम होता जायगा। क्योंकि जिसके भीतर जरा-सा भी आनन्द आया, उसके बाहर स्वीकृति आने लगती है, वह चीजोंको स्वीकार कर संतुष्ट होने लगता है। यदि स्वधर्मके अनुकूल न चलता हो तो अस्वीकार बढ़नेके साथ ही असंतुष्ट होता चला जाता है। हर चीजके प्रति दुश्मनकी दृष्टि आ जाती है। तीसरा सूत्र यह कि स्वधर्मके अनुकूल यदि जाना हो तो सिर्फ बाहरकी चीजोंमें उलझकर कोई व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। दैनिक कामोंमें पता ही नहीं चलता कि स्वधर्म क्या है। परधर्म क्या है। जिसे स्वधर्मकी खोज करनी हो, उसे बाहरकी दुनियासे कमसे कम चौबीस घंटेमें घंटेभरके लिए बिलकुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतरकी दुनियामें डूब जाना चाहिए। बाहरके द्वार बंद कर देने चाहिए। सब इंद्रियोंके द्वार बंद करके अपने भीतर घंटेभरके लिए डूब जाना चाहिए। वहीं स्वयं और निजताके रहस्यका पता चलेगा उस रहस्यका जो अपना है। वहींसे सूत्र मिलेंगे, ध्वनि सुनायी पड़ेगी, वहींसे इशारे मिलेंगे। धीरे-धीरे इशारे गहरे होते चले जाते हैं। यह आखिरी सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वधर्मका पता अन्दरकी वाणीके अतिरिक्त और कहींसे नहीं चलता है। चौथा सूत्र है अपने स्वधर्मके केन्द्रको छू लेना। बाहरकी दुनियाको बंद करके सब भूलकर जब अपने भीतर डुबकी लगायेंगे तो उस डुबकीमें धीरे-धीरे भीतरकी अंतर्वाणी सुनाई देनी शुरू होगी। यह अंतर्वाणी सबके भीतर छिपी है। यह बहुत छोटी-सी आवाज है, एकदम धीमी, नाजुक और सूक्ष्म। इसे केवल वही सुन सकते हैं, जो उतनी सूक्ष्म आवाजको सुननेके लिए अपनेको प्रशिक्षित करते हैं। स्वधर्मकी खोजके लिए रोज एक घंटा तय कर लें। अंतरात्माको स्वधर्म अच्छेसे पता है। आंख बंद करें। मौन हो जायं। चुप बैठकर सुनें। अपने मनकी आवाजको सुनो और ध्यानसे उसपर गौर करें। आपको अपने अन्दर एक अलग ही ध्वनि सुनाई देगी, जिसमें डूब कर आप अपनेको पहचान सकते हो। मौन धारण करके देखो। जीवनमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आयें, मनुष्यको अपने मार्गसे नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करनेके लिए मनमें दृढ़ संकल्पके साथ-साथ अग्रसर होनेके लिए अंतरात्माकी आवाजको सुनना जरूरी है। हमेशा अपने लक्ष्यपर ध्यान केंद्रित करें।

जहरीली हवासे गहराता स्वास्थ्य संकट

❐ कांतिलाल मांडोत

देशकी राजधानी दिल्लीमें वायु प्रदूषणकी समस्या एक बार फिर गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। दीपावलीके बाद वातावरणमें बढ़ती धुंध और जहरीले प्रदूषक कणोंने आम जनजीवनको प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हालात यह हैं कि दिल्लीके कई इलाकोंमें वायु गुणवत्ता सूचकांक ४०० के पार पहुंच गया है। यह केवल राजधानीकी समस्या नहीं है, बल्कि देशके पर्यावरणीय संतुलनपर मंडराते खतरेका संकेत है। दुनियाके सर्वाधिक प्रदूषित ५० शहरोंमें ४९ शहरोंका भारतमें होना हमारी विकास व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जिम्मेदारीपर गम्भीर सवाल खड़े करता है। राजस्थानके श्रीगंगानगरमें एक्यूआईका ८२१ तक पहुंचना इस संकटकी व्यापकताको दर्शाता है। दिल्लीमें प्रदूषणका बढ़ना अब हर वर्ष दोहराई जाने वाली समस्या बन गया है। सर्दियोंकी शुरुआत होते ही हवाकी गुणवत्ता गिरने लगती है। सड़कोंपर दौड़ते लाखों वाहन, निर्माण कार्योंसे उड़ने वाली धूल, औद्योगिक इकाइयोंका उत्सर्जन, खुलेमें कचरा जलाना और आसपासके राज्योंमें कृषि अवशेषोंका प्रबंधन नहीं होना भी प्रदूषणके प्रमुख कारणोंमें शामिल हैं। मौसममें बदलाव और हवाकी गति कम होनेसे प्रदूषक तत्व वातावरणमें जमा रहने लगते हैं। यही कारण है कि राजधानीकी हवा कुछ दिनोंमें ही सांस लेनेके लिए चुनौती बन जाती है। सबसे चिन्ताजनक पहलू यह है कि प्रदूषणका प्रभाव किसी विशेष वर्गतक सीमित नहीं रहता। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पहलेसे सांस या हृदय संबंधी परेशानियोंसे जूझ रहे लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लगातार दूषित हवामें रहनेसे फेफड़ोंकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आंखोंमें जलन, खांसी, सांस लेनेमें परेशानी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। गम्भीर प्रदूषणका असर स्वस्थ व्यक्तियोंपर भी पड़ सकता है। जिस हवाको जीवनका आधार माना जाता है, वही जब स्वास्थ्यके लिए खतरा बनने लगे तो इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझना बड़ी भूल होगी।

वायु गुणवत्ता सूचकांकके अलग-अलग स्तर प्रदूषणकी स्थितिको समझनेमें मदद करते हैं। २०१ से ३०० तक एक्यूआई खराब, ३०१ से ४०० तक बहुत खराब और ४०१ से ५०० तक गम्भीर श्रेणीमें आता है। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन और हरियाणाके बहादुरगढ़में भी प्रदूषणका स्तर ४०० के पार पहुंचनेकी जानकारी सामने आयी है। उत्तर प्रदेशके नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद जैसे शहरोंमें भी हवाकी गुणवत्ता खराब दर्ज की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदू